

पंजाब: बादल गांव में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, आप ने कैप्टन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

By Kapil Tiwari | Updated: Monday, May 24, 2021, 12:07 [IST]



चंडीगढ़, मई 24। पंजाब के बादल गांव में पकड़े गए गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के यूथ विंग के प्रधान और विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस कार्रवाई की आड़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर निशाना साधा है। मीत हेयर ने कहा कि कैप्टन की सरकार में भी बादलों के घर से ही नशे का कारोबार चल रहा है।

चार साल बीत गए पर कांग्रेस नहीं पूरा किया अपना वादा: आप

दरअसल, शिरोमणि अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के गांव 'बादल' में गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसी संबंध में आप के मुख्य दफ्तर से रविवार को बयान जारी किया गया। मीत हेयर ने सीएम कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि, 'कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने मालवे की धरती पर श्री गुटका साहिब की कसम खा कर पंजाब के लोगों के साथ वायदा किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर चार हफ्तों में ही नशा माफिया का खत्म किया जायेगा, लेकिन चार साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद कैप्टन अमरेन्द्र सिंह प्रदेश से नशा खत्म नहीं कर सके।'

'शराब के कारण हो रही मौतों से कांग्रेस बेपरवाह'

उन्होंने आगे कहा कि बादलों के घर से चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री अगर पकड़ी नहीं जाती तो इसके चलते कभी भी बादल गांव समेत मालवा में दुखद हादसा हो सकता था। हेयर ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को 'बादलों की ओर से शुरू किये गए नकली शराब के कारोबारियों की ही सरकार' बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार को अवैध शराब के कारण हो रही मौतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि नाजायज शराब पीकर मरने वाले तो आम परिवारों के सदस्य हैं।

पंजाब और हरियाणा कोर्ट के जज से कराई जाए जांच

इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि बादल गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़े जाने की पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मौजूदा जज से जांच करवाई जाये। इससे यह कारोबार करने वालों की राजनैतिक लोगों के साथ हिस्सेदारी सामने आ सकेगी।

Source: <https://hindi.oneindia.com/news/punjab/punjab-fake-liquor-factory-busted-in-badal-village-aap-allegations-against-captain-govt-619519.html?story=1>